

**U.N.I.****F.N.P.O.****I.N.T.U.C**

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं  
और डाक कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे  
FNPO-NUPE Postmen & Group-D/MTS Union कहते हैं।



# POSTAL PRAKASH



सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/-

Single Copy Rs. 5/-

Editor : T.N. RAHATE

Vol. No. XXXII - No. 7

JULY, 2016

## HINDI ISSUE

### Contents

**Page 1**

It was Expected

**Page 2**

Newly Elected Circle Office Bearers of NUPE P-IV,  
Postmen & MTS, Maharashtra and Goa Circle

**Page 4**

GDS आयोग

**Page 10**

Strike is Deferred,  
but the Struggle shall continue

**Page 11**

Even chance for issue of 7th CPC  
Implementation Notification

**Page 13**

CGHS Rates for Cancer Surgery for  
hospitals empanelled under CGHS

**Page 14**

सैलरी बढ़ाने के मुद्दे पर मोदी सरकार ने  
इसलिए दांव पर लगा दी अपनी लोकप्रियता...

**Page 15**

7वें वेतन आयोग में उलझे हैं तो इस खबर को  
जरूर पढ़ें, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब यहां हैं

**Page 16**

Gazette Notification for  
Implementation of 7th CPC

## It was Expected.

*Desh ke heet me karenge kaam*

*lekin kaam ka nahi milega pura daam*

When Shri Manmohan Singhji our Ex-Prime Minister announced to constitute 7th Pay Commission for C.G. Employees, Shri N.D. Modi our present Prime Minister who was Chief Minister of Gujarat at that time, strongly opposed for formation of 7th CPC.

Unfortunately, he became Prime Minister of India and as expected he has shown his anger towards C.G. Employees through the implementation cell on recommendations of 7th CPC who has not made any modification on the anti-labour recommendation of 7th CPC. The minimum wage recommendation of Rs. 18,000/- is not as per market index and the justified demand of Rs. 23,000/- has been turned down by the Government headed by Mr. Modi.

We must note that the C.G. Employees Unions has already protested against the 7th CPC recommendation and asked Government to modify them and gave the Strike Notice in advance. But the Government has not accepted our demand and we are forced to go on Indefinite Strike from 11th July, 2016. We all must shut down total Government machinery from 11th July 2016 which is run by C.G. Employees.

NJCA team met Shri Rajnath Singh, Hon. Home Minister. He assured formation of the Committee, on this base NJCA decided to defer the Strike for further months.

**जोर-जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है।**

**- T.N. Rahate**

**Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'D'/MTS**

P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. Tel.: 23818330 • Email : tnrahate@yahoo.com

**Shri T.N. Rahate** (General Secretary) M.: 08080070500, 09869121277

**Web :** www.nupestmen.org • www.nupestmenp4.blogspot.com

---

**List of Newly Elected Circle Office Bearers of  
NUPE P-IV, Postmen & MTS, Maharashtra and Goa Circle**

---

भारतीय डाक विभाग  
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA  
चीफ पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय  
O/o The Chief Postmaster General,  
महाराष्ट्र सर्किल, मुंबई-400 001  
Maharashtra Circle, Mumbai-400 001

To

- 1) All PMsG in Maharashtra Circle
- 2) The Director, Mumbai GPO, Mumbai-400001
- 3) All SSPOs/SPOs, in Maharashtra Circle
- 4) All CSDs/PSDs in Maharashtra Circle
- 5) the A.D. P.S. (A&V), Fgn. Post, Mumbai-400001

No: Union/26-2/P-IV/2016 Mumbai-400001 the 01.07.2016

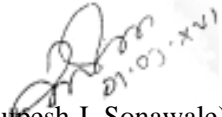
**Subject :** Regarding approval from NUPE Postman & MTS, CHQ, New Delhi-110054 to the list of newly elected Circle Office Bearers of NUPE P-IV, Postmen & MTS, Maharashtra and Goa Circle.

It has been intimated by Sunil P. Zunjarrao, Circle Secretary, NUPE P-IV vide letter No. NU/P-IV/Circle Conference/MH/1/2016-18 dated 13.06.2016 that, following new Circle Office Bearers have been elected on 06.06.2016 at Mahad, Raigad for the period 2016-18.

Sl. Post	Name	Designation	Office of Working
1. <b>President</b>	<b>Shri T.N. Rahate</b>	Postman	Tank Road PO, Mumbai-400033
2. Working President	<b>Shri R.N. Awate</b>	Overseer	Malad (W) PO, Mumbai-400064
3. Vice President	Shri S.Y. Jadhav	Overseer	Azadnagar PO, Mumbai-400053
4. Vice President	Shri R.R. Shinde	Postman	Gandhi Nagar PO, Nasik-6
5. <b>Circle Secretary</b>	<b>Shri Sunil P. Zunjarrao</b>	Postman	O.E. Ambernath PO-421502
6. <b>Dy. Circle Secretary</b>	<b>Shri Santosh Y. Lad</b>	Postman	Mahim HO, Mumbai-400016
7. Asstt. Circle Secretary	Shri Uttam Waghmare	Stg. Postman	Nerul Nod. PO, Navi Mumbai-400706
8. <b>Asstt. Circle Secretary</b>	<b>Shri N.N. Mujawar</b>	Postman	Kolhapur HO-416003
9. Asstt. Circle Secretary	Shri P.S. Shinde	Stg. Postman	Model Colony PO, Pune-411016
10. Asstt. Circle Secretary	<b>Shri V.B. Ahire</b>	Mail Overseer	Aurangabad HO-431001

11. Organising Secretary	<b>Shri E.A. Baruva</b>	Postman	Parwati Nagar PO, Nagpur-440027
12. Organising Secretary	<b>Shri D.R. Devkar</b>	Postman	Chinchvad (E), Pune-411019
13. Organising Secretary	Shri Sudhir Garibe	Postman	Marine Lines PO, Mumbai-400020
14. <b>Circle Treasurer</b>	<b>Shri S.G. Kalokhe</b>	Postman	Mumbai GPO, Mumbai-400001
15. Asstt. Treasurer	Shri V.B. Hivrale	Cash Overseer	Akola HO-444001

Necessary Trade Union facilities may be extended to the above Office Bearers of the above said Union.

  
(Rupesh J. Sonawale)

Asstt. Director Postal Services (PSR)  
O/o The Chief Postmaster General,  
Maharashtra Circle, Mumbai-400001.  
Email ID : [adpsrmh@gmail.com](mailto:adpsrmh@gmail.com)  
Tel No. 226232330/22621806

Copy to:  
Sunil P. Zunjarrao  
Circle Secretary, NUPE P-IV,  
Maharashtra & Goa Circle,  
O.E. Ambernath PO-421502

## ये तो होना ही था

7वे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ मंत्री मंडल सचिवों की कमेटी के समक्ष केंद्रिय कर्मचारियों के संगठन द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया था तथा इस कमेटी के साथ वार्तालाप द्वारा भी कर्मचारियों की ओर से वेतन आयोग द्वारा दी गयी रिपोर्ट के विरुद्ध तथा न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग तथा अन्य कर्मचारी विरोधी सुझावों को रद्द करने तथा कुछ सुझावों में पुर्नगठन की मांग प्रस्तुत की गयी थी तथा 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय में जो नोटिस दिया गया है उस पर भी चर्चा की थी।

किंतु प्रचलित सरकार द्वारा मंत्री मंडलीय सचिवों की कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि कमेटी वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई सुधार न करे और इस लिए हम कर्मचारियों को इस विषय को गंभीरता से लेना है कि पिछली सरकार ने 6वे वेतन आयोग की रिपोर्ट में सकारात्मक सुधार किये थे किंतु यह सरकार मजदूर विरोधी होने के कारण आज हम पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल थोपी गयी है। हमें हर हाल में हमारी जायज मांगों को इस सरकार से लेना ही होगा। यह देश इस भा.ज.पा. सरकार को 5 साल के लिए चलाने को दिया गया है। यह देश इस पार्टी को इनाम में नहीं दिया गया है। ये हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते क्योंकि आप सब जागरूक हैं।

NJCA टीम श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री से मिली। उन्होंने कमेटी बनाने के लिए हामी भरी। इस आधार पर NJCA ने हड़ताल कुछ महीनों के लिए स्थगित किया है।

**हम को मिटा सके ये सरकार में दम नहीं  
सरकार हमारे दम से है हम सरकार से नहीं।**

- टी.एन. रहाटे

---

## GDS आयोग

---

### FNPO

#### National Union of Gramin Dak Sevaks

#### Central Head Quarters

T-24, Atul Grove Road, New Delhi - 110 001. Phone : 011-23321378, 09446436592

---

28-05-2016

### GDS आयोग

NU GDS/FNPO संयुक्त रूप से GDS आयोग को पेश किया गये ज्ञापन के अनुरूप 27-5-2016 को आयोग चेयरमैन के साथ की गयी चर्चा में हमने निम्नलिखित मुद्दों उठाये हैं -

1. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर शाखाओं को भविष्य में महत्व देना।
2. GDS कर्मचारियों का स्वाभीमान बनाये रखना।
3. GDS कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं पर विचाराधीन।
4. GDS कर्मचारियों से संबंधित अदालती मुकदमों।
5. GDS कर्मचारियों को संविधान के अनुरूप मिलने वाले सिविल सेवादर का दर्जा।
6. विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले GDS कर्मचारियों का काम तथा जवाबदारी, और उनके समान कार्य करने वाले विभागीय कर्मचारियों का काम और जवाबदारी के अंतर का अवलोकन करना।
7. GDS कर्मचारियों का वेतन तथा विभागीय कर्मचारियों का वेतन के अंतर पर स्पष्टीकरण।
8. GDS कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाले सभी कार्यों को पूर्ण कार्य का दर्जा देना।
9. GDS कर्मचारियों का कार्य समय साढ़े सात घंटे निर्धारित करना।
10. GDS कर्मचारियों और केन्द्रीय कर्मचारियों के बीच नई पेंशन योजना के अंतर का अवलोकन।
11. नई पेंशन योजना में GDS कर्मचारियों को भी शामिल करने का आवश्यकता।
12. देश में 65 वर्ष पूर्ण करने वालों को मिलने वाला प्रधानमंत्री बुजुर्ग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाला 1000/- रुपये, नगरपालिका और पंचायत में मिलने वाला बुजुर्ग पेंशन, GDS कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन मिलने को योग्य होने संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता।
13. GDS कर्मचारियों को मिलने वाले प्रसूती वेतन समय पर बढ़ाने संबंधी।
14. GDS कर्मचारियों के प्रसूती वेतन को कल्याण कोष से हटाकर बजट में प्रावधान रखना।
15. महिला GDS कर्मचारियों के लिए डाक घरों में शौचालयों का निर्माण करने संबंधित।
16. शाखा डाक घरों का किराया, बिजली बिल का भुगतान डाक विभाग द्वारा ही करने।
17. डाक घरों को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए कम से कम 4 वर्षों में एक बार पेंटिंग कराने का खर्च डाक विभाग द्वारा किये जाने के विषय में।
18. देश के सभी डाक घर शाखाओं को एक समान रूप देने।
19. डाक घर शाखाओं आने वाले आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए वित्तीय पैकेज देने।
20. दो वर्षों में एक बार डाक घर और आम जनता के सहयोग से मेलाओं को आयोजित करने।
21. डाक घरों का FSC, विभागीय C-Class कार्यालयों के समान देने संबंधित।

22. ग्रुप बीमा राशि एक लाख तक बढ़ाने।
23. सेवानिवृत्त पर ग्रज्युअटी सीमा समाप्त करके ज्यादा से ज्यादा 5 लाख करने।
24. GDS कर्मचारियों का Ex-gratia grativity को हटाकर grativity एक्ट के अनुरूप प्रदान करने।
25. ग्रेटिविटी बनाते समय डी.ए. को भी शामिल करना।
26. वर्तमान डी.ए. प्रावधान को यथास्थित रखने।
27. वर्तमान बोनस प्रावधान को यथास्थित करना।
28. इंक्रीमेंट 5%।
29. GDS BPM का नाम बदलकर ग्रामीण पोस्ट मास्टर (RPM) रखने तथा सभी GDS कर्मचारियों का नाम समन्वय कराकर ग्रामीण डाक सहायक (RPA) रखने का मांग।
30. अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को मिलने वाले रोजगार के लिए कानून बनवाने।
31. GDS कर्मचारियों और उनके परिवारों को सरकारी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए नियम बनवाने।
32. शारीरिक कारणों से काम नहीं कर सकने वाले GDS कर्मचारियों को चिकित्सा बोर्ड के सिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्त होने का अवसर तथा उनके आश्रितों को नौकरी मिलने संबंधित नियम बनाने।

**नीचे दर्शाये गये हिसाब से वेतन स्केल 10, 20, 30 वर्षों में  
पहला, द्वितीय एवं तृतीय MACP देने की मांग।**

14.14 Initial fixation to RPAs/RPMs as follows at the time of implementation of 7th PC.

**Rural Postal Assistant :**

Upto 5 years	18,000 + GP
After 5 years	18,000 + 1 increment i.e. 5% on 18,000 + GP
After 10 years (MACP I)	18,000 + 3 increment i.e. 15% on 18,000 + GP (For MACP I one more increment)
After 15 years	18,000 + 4 increments i.e. 20% on 18,000 + GP
After 20 years (MACP II)	18,000 + 6 increment i.e. 30% on 18,000 + GP (For MACP II one more increment)
After 25 years	18,000 + 7 increment i.e. 35% on 18,000 + GP
After 30 years (MACP III)	18,000 + 9 increment i.e. 45% on 18,000 + GP (For MACP III one more increment)
After 35 years	18,000 + 10 increments i.e. 50% on 18,000 + GP i.e. 18,000 + 9,000 = 27,000 which is less than proposed pay component of MTS i.e. 29,000 which is a promotional post. If this is not followed there will be no charm in promotions.

---

**Rural Post Master :**

To show difference between RPA and RPM 2 increments may be given at initial stage of fixation of RPM also. Then,

Upto 5 years	18,000 + 2 increments i.e. 10% on 18,000 + GP
After 5 years	18,000 + 3 increment i.e. 15% on 18,000 + GP
After 10 years (MACP I)	18,000 + 5 increment i.e. 25% on 18,000 + GP (For MACP I one more increment)
After 15 years	18,000 + 6 increments i.e. 30% on 18,000 + GP
After 20 years (MACP II)	18,000 + 8 increment i.e. 40% on 18,000 + GP (For MACP II one more increment)
After 25 years	18,000 + 9 increment i.e. 45% on 18,000 + GP
After 30 years (MACP III)	18,000 + 11 increment i.e. 55% on 18,000 + GP (For MACP III one more increment)
After 35 years	18,000 + 12 increments i.e. 60% on 18,000 + GP i.e. 18,000 + 10,800 = 28,800 which is less than proposed pay component of MTS i.e. 29,000 which is a promotional post. If this is not followed there will be no charm in promotions.

14.15 No bunching is suggested as it is not giving any room for any anomaly at any stage.

14.16 The above fixation is suggested for initial fixation on implementation of 7th PC. Thereafter normal procedure may be followed i.e. giving every increment after completion of every year of service from the date of implementation i.e. 1 year after 01-01-2016 i.e. from 01-01-2017, following the length of service as mentioned in para 14.14.

14.17 Grade Pay : Grade Pay to RPA/RPM is as follows in 7th PC.

At present MTS at initial stage is on 1800 GP. In 7th PC his pay suggested by Federations is 33,000/- i.e. as 29,000/- pay component and 4000 GP component as discussed at para 14.8. The presumptive Grade pay at the minimum to Rural Postal Assistants / Rural Post Masters was given at para 14.9. 1800 GP of MTS was proposed as 4000 GP component in 7th PC.

As such Grade Pay for Rural Postal Assistants and Rural Post Masters in 7th PC is suggested as follows.

---

**Rural Postal Assistants :**

At initial stage	$4000 \times 1000 / 1800 = 2222$ i.e. 2200
On MACP I (after 10 years of service)	$4000 \times 1100 / 1800 = 2444$ i.e. 2400
On MACP II (after 20 years of service)	$4000 \times 1200 / 1800 = 2666$ i.e. 2600
On MACP III (after 30 years of service)	$4000 \times 1300 / 1800 = 2888$ i.e. 2900

**Rural Post Masters :**

At initial stage	$4000 \times 1400 / 1800 = 3111$ i.e. 3100
On MACP I (after 10 years of service)	$4000 \times 1500 / 1800 = 3333$ i.e. 3300
On MACP II (after 20 years of service)	$4000 \times 1600 / 1800 = 3555$ i.e. 3500
On MACP III (after 30 years of service)	$4000 \times 1700 / 1800 = 3777$ i.e. 3800

In all the above cases it is rounded off to next hundred and whereas in the case of MACP II it is rounded off to below hundred to remove the dissatisfaction to MACP III candidates. However proposed GP to RPA/RPM is less than proposed GP component of MTS i.e. Rs. 4,000/-

**14.18 Length of Pay Scale :** For this minimum pay proposed for RPA is 18,000 and RPM 18,000 plus 2 increments. If span of 36 years in 6th PC taken as base it will be  $36 + 2 = 38$  years and almost all will retire by 38 years. If not they will have to stay at stagnation as stagnation increments cannot be suggested in this running scale. Moreover span of 38 years will be somewhat reduced by maximum 12 increments due to allowing one increment added for every 5 years and one more increment is added for each MACP besides giving 2 increments as initial fixation of Rural Post Master. However, proposed minimum pay on initial fixation i.e. Rs. 18,000/- is taken as base. Then span of pay scale will be as follows with 5% raise every year due to allowing increments. For 36 years span the GP was also taken in 6th PC, whereas GP earn increments the minimum Pay for RPA 18,000 + GP 2200 is taken as base though there are proposed GPs ranging between 2200 to 3800.

**14.19 Increments :** Increment is 5% on basic pay every year besides MACP I, II, II promotions. This is in addition to 2 increments i.e.  $5 + 5 = 10\%$  allowed to Rural Post Masters on initial fixations.

14.20 Maximum of pay scale for RPA and RPMs get together as per incrementation mentioned in para 14.19.

At intial entry pay 18000 + GP 2200 = 202000.

	<b>Pay x Raise</b>	<b>=</b>	<b>Pay + Raise</b>	<b>=</b>	<b>Total</b>
At initial entry	-	=	20200	=	20,000
After 1st increment	20200 x 5%	=	202000 + 1010	=	21210
After 2nd Increment	21210 x 5%	=	21210 + 1061	=	22271
After 3rd Increment	22271 x 5%	=	22271 + 1114	=	23385
After 4th Increment	23385 x 5%	=	23385 + 1169	=	24554
After 5th Increment	24554 x 5%	=	24554 + 1228	=	25782
After 6th Increment	25782 x 5%	=	25782 + 1289	=	27071
After 7th Increment	27071 x 5%	=	27071 + 1354	=	28425
After 8th Increment	28425 x 5%	=	28425 + 1421	=	29846
After 9th Increment	29846 x 5%	=	29846 + 1492	=	31338
After 10th Increment	31338 x 5%	=	31338 + 1567	=	32905
After 11th Increment	32905 x 5%	=	32905 + 1645	=	34550
After 12th Increment	34550 x 5%	=	34550 + 1728	=	36278
After 13th Increment	36278 x 5%	=	36278 + 1814	=	38092
After 14th Increment	38092 x 5%	=	38092 + 1905	=	39997
After 15th Increment	39997 x 5%	=	39997 + 2000	=	41997
After 16th Increment	41997 x 5%	=	41997 + 2100	=	44097
After 17th Increment	44097 x 5%	=	44097 + 2205	=	46302
After 18th Increment	46302 x 5%	=	46302 + 2315	=	48617
After 19th Increment	48617 x 5%	=	48617 + 2431	=	51048
After 20th Increment	51048 x 5%	=	51048 + 2552	=	53600
After 21st Increment	53600 x 5%	=	53600 + 2680	=	56280
After 22nd Increment	56280 x 5%	=	56280 + 2680	=	59094
After 23rd Increment	59094 x 5%	=	59094 + 2955	=	62048
After 24th Increment	62048 x 5%	=	62048 + 3102	=	65150
After 25th Increment	65150 x 5%	=	65150 + 3257	=	68407
After 26th Increment	68047 x 5%	=	68047 + 3402	=	71449
After 27th Increment	71449 x 5%	=	71449 + 3572	=	74621
After 28th Increment	74621 x 5%	=	74621 + 3731	=	78352
After 29th Increment	78352 x 5%	=	78352 + 3918	=	82269
After 30th Increment	82269 x 5%	=	82269 + 4113	=	86382
After 31st Increment	86382 x 5%	=	86382 + 4319	=	90631
After 32nd Increment	90631 x 5%	=	90631 + 4532	=	95183
After 33rd Increment	95163 x 5%	=	95163 + 4758	=	99921



After 34th Increment	99921 x 5%	=	99921 + 4996	=	104917
After 35th Increment	104917 x 5%	=	104917 + 5256	=	110163
After 36th Increment	110163 x 5%	=	110163 + 5508	=	115871
After 37th Increment	115671 x 5%	=	115671 + 5783	=	121454
After 38th Increment	121454 x 5%	=	121454 + 8073	=	127527
					Say 128000

14.21 As per para 14.20 the maximum of the scale is 128000 given 38 years span covering full length of service. This appears to be high but scientific. In earlier commissions uniform increment was given based on initial stage of the scale. Say suppose for basic pay 18000 + Grade Pay 2200, increment for 20200 was assessed initially as 1010 and was continued for all the 38 years. Then increment earning for 38 years was  $1010 \times 38 = 38380$ . Then maximum would be  $20200 + 38380 = 58580$ . Now it is doubled due to consideration of 6th PC granting 3% which was now suggested as 5% raise every year on basic pay + Grade pay what was drawn a day before instead of giving uniform annual increase. As such calculation of maximum is purely scientific and span of 38 years, maximum of 128000 and running scale of 18000-128000 with 5% raise every year on pay + grade pay drawn in the previous year qualifies for increment may be considered.

14.22 Pay band should be pay band I shifting other pay bands by one number or giving special pay band, i.e. pay band R is suggested for Rural Post Masters and Rural Postal Assistants.

14.23 Thus proposed wage structure covering all aspects in this chapter XIV is requested to be considered.

चर्चा में आयोग की ओर से चैयरमैन श्री कमलेश चंद्र, सचिव श्री टी.क्यू. मोहम्मद, सहायक महानिदेशक श्री के.के. जयशंकर और यूनियन की ओर से महासचिव पी.यू. मुरलीधरन, सेक्रेटरी जनरल श्री डी. त्यागराजन, NAPE ग्रुप सी महासचिव श्री डी. किशन राव, NUPE पोस्टमैन, MTS महासचिव श्री टी.एन. रहाटे, NAPE ग्रुप सी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रजत एस. दास, NU GDS राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सी.एच. लक्ष्मी नारायण, श्री बी. शिवकुमार ने भाग लिया।

चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में चला और आयोग चैयरमैन एवं सदस्यों की ओर से सकारात्मक रवैया रहा और उनके द्वारा बीच में उठाये गये सवालों को उचित तरीके से उत्तर प्रस्तुत करने में हम सफल रहे हैं।

आखिर में हमने उन्हें यह भी बताया कि GDS कर्मचारी अभी भी न्यायमूर्ति श्री चरणजीत सिंह तलवार को याद करते हैं, और GDS कर्मचारियों का भविष्य भी आप को हमेशा स्मरण करते रहने जैसे सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ चर्चा समाप्त की गयी।

सुबह 10.30 बजे से आरंभ चर्चा दोपहर एक बजे समाप्त हुई।

पी. यू. मुरलीधरन  
(महासचिव)

---

## Strike is Deferred, but the Struggle shall continue

---

DATED - 07.07.2016

### Strike is Deferred, but the Struggle shall continue

Finally, the united struggle of 33 lakhs Central Government Employees under the banner of National Joint Council of Action (NJCA) comprising Railways, Defence has compelled the totally negative and unwilling NDA Government to negotiate with the staff side leaders. Hon'ble Prime Minister has intervened and directed three Cabinet Ministers viz. Home Minister **Shri Rajnath Singh**, Finance Minister **Shri Arun Jaitly** and Railway Minister **Shri Suresh Prabhu** to hold discussion with the NJCA Leaders on 30th June 2016. After discussing the demands raised in the Charter of demands, the Ministers assured that a high level committee will be constituted to consider the demands raised by NJCA especially the demand for improving the minimum wage and fitment formula.

As no written communication or minutes regarding the assurances given by Group of Ministers is forthcoming, the NJCA met again on 6th July and decided to go ahead with the strike decision. Again Home Minister **Shri Rajnath Singh** called the NJCA leaders for discussion on 6th July and reiterated the assurances already given on 30th June and stated that the Finance Minister will issue a press statement on 6th July itself confirming the assurances given by the Group of Ministers. It was further assured by the Minister that the proposed High level committee will submit its recommendations to Government within a time frame.

Accordingly, the Government issued the press statement and after detailed deliberations the NJCA unanimously decided to defer the Indefinite Strike till the Committee finalizes its report. The press statement of the NJCA and the Government are attached.

#### CHQ Quota

All the Divisional Secretaries /  
Branch Secretaries are requested to send  
CHQ Quota of **Rs. 10/- (Rs. Ten)**  
each member per month to  
**Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ),**  
**Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002.**  
M.: 09911 226062 / 09899 608399 /  
08595 045985 as early as possible.

#### सी.एच.क्यू कोटा

सभी डिवीजनल सेक्रेटरी / ब्रांच सेक्रेटरी से  
अनुरोध किया जाता है CHQ कोटा  
रुपये **10/- (दस रुपये)** प्रति मेंबर प्रतिमाह भेजें।  
यह चंदा दर दिसंबर 2014 से लागू है।  
**CHQ कोटा श्री जगदीश शर्मा, खंजाजी (CHQ),**  
कैम्प : आई.पी.एच.ओ. नयी दिल्ली-110002  
मो.: 09911 226062 / 09899 608399/  
08595 045985 को जल्द-से-जल्द से भेजें।

---

## Even chance for issue of 7th CPC Implementation Notification

---

### 7th Pay Commission - Even chance for issue of 7th CPC Implementation Notification

Now that Government avoided Strike Action over modification of 7th Pay Commission report. Will it go ahead with its implementation plans now?

7th Pay Commission - Even chance for issue of 7th CPC implementation Notification pending submission of reports by Committees for Allowances, Minimum Pay and Fitment Formula.

After Cabinet decided to approve recommendations of 7th Pay Commission on 29th June 2016, without any change in the quantum of allowances for time being, Finance Ministry was working on hectic pace to issue notification.

This notification is meant for framing revised Pay Rules for new 7th CPC Basic Pay and retirement benefits such as Pension, Gratuity etc., with suitable provisions for paying allowances in pre-revised pay till Government decides on the report of Allowances Committee. The report of Allowances Committee is expected to be submitted in 4 months.

However, after widespread disappointment and protests over revised minimum pay and fitment formula, Council of Ministers conducted overnight talks with Union/Staff Side Association leaders on 30th June, 2016.

During the meeting, the Council of Ministers promised for constituting a Committee to look into Minimum Pay and Fitment Formula.

Needless to say, this was a prudent move of Government to avoid Indefinite Strike planned by all Central Government Employees and Railway Employees from 11th July 2016.

### Highlights

## Recommendations of 7th Central Pay Commission

**Minimum pay : Rs. 7000 to Rs. 18000 p.m.**

**Lowest starting salary for newly recruited employee : Rs. 18000**

**For a freshly recruited Class I Officer : Rs. 56100**

- Status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the Pay Matrix
- No new levels introduced, no level dispensed with
- **Fitment Factor** of 2.57 will be applied across all levels for revision of pay and pension
- Rate of increment retained at 3%
- Further improvements in Defence Pay Matrix by enhancing Index of Rationalisation approved
- **Gratuity Ceiling** - from Rs. 10 to 20 lakh, will increase by 25% whenever DA rises by 50%
- A common regime for payment of **Ex-gratia** lumpsum compensation for civil and defence forces personnel payable to next of kin with the existing rates enhanced from Rs. 10-20 lakhs to 25-45 lakh for different categories
- Ceiling of House Building Advance advanced from Rs. 7.50 lakh to 25 lakh

---

On 6th July, 2016 Government has issued a press release to the effect that it would form a high level Committee to review the 7th Pay Commission recommended Minimum Pay and Fitment Formula once again.

Now, it remains to be seen whether Government would issue Notification for implementation of 7th Pay Commission recommendations in the lines of Cabinet for the same on 29th June 2016, pending submission of reports by Committees formed/yet to be formed, to study the need for revising allowances, Minimum Pay and Fitment Formula more than what was recommended by 7th Pay Commission.

Highly placed sources say, there are even chances for the issue of Notification for implementing the 7th Pay Commission recommendations pending submission of reports by Committees.

Government may take such a decision in order to implement 7th Pay Commission recommendations well prior to start of model code of conduct in respect of Assembly Elections in major states such as Punjab, Uttarakhand etc.

Assembly Elections are due in March 2017 for four States viz. Punjab, Uttarakhand, Manipur and Goa. The term of State Government in Uttar Pradesh ends in the month of May 2017.

Alternatively, Government will have to issue Notification for implementation of 7th Pay Commission recommendations.

### **Doubts & Clarifications**

We are receiving mails and telephonic calls from various levels about 7th CPC. Our Federation clarifies the doubts after consulting top NJCA leader.

1. When Government issued 7th CPC implementation notification?  
It is clarified that the Gazette notification will be issued by the Government by the end of July, 2016 and Central Government Employees will get 7th CPC Salary in the month of August, 2016.
2. What is the recommendation of empowered Committee Chaired by Cabinet Secretary?  
Committee recommendation is not disclosed for NJCA leaders. But it is visible, report is not accepted by the NDA Government.
3. What is the present High Level Committee?  
The present Committee consists of Group of Ministers which includes Finance Minister; Home Minister and Railway Minister, this Committee submits its opinion within 4 months.
- 3a. If the New Committee rejected our demand what is the stand of NJCA?  
It is clarified by the NJCA that deferred Indefinite Strike will revive.
4. What is rate of HRA and other allowances?  
According to announcement the HRA will be paid in the ratio of 30%, 20%, 10% for another 4 months and remaining allowances will be paid in the rates in existing pay structure. High level Committee will take final discussion within time frame of 4 months.

- 
5. Whether better settlement is possible if we went on Strike on the proposed date of July 11, 2016?  
We cannot presume things on assumption basis, but it is sure Government will abide by when only Railway men go on Strike. We are only minority partners. We cannot do any major role in the NJCA.
6. What about the pension in regard to parity?  
The Finance Minister categorically assured that the Government has accepted the recommendations in toto and the Pension Department has been asked to sort out the difficulties in implementation.
7. What is the fate of GDS demand?  
Postal Unions demand proportionate scales for GDS Employees, hence the minimum wage is important to fix salary to GDS.  
In the Kamlesh Chandra Committee FNPO & NU GDS demand regularization of GDS Employees by giving full justification. FNPO will continue its efforts to get status to GDS like earlier we will not talk much about GDS but FNPO will do everything as in the case of past.
- 

### **CGHS Rates for Cancer Surgery for hospitals empanelled under CGHS**

...(Contd. from Postal Prakash, June 2016, Pg. 7)

#### **Gradation of surgical procedures for treatment of cancer**

Sr.	Surgery Grade V	Grade
	<b>Thoracic &amp; Paediatric</b>	
23.	Bronchial + Vascular Sleeve	Grade V
24.	Radical Nephrectomy (Paed.) + Bowel Excl.	Grade V
25.	Retroperitoneal Tumor + Bowel Excision	Grade V
26.	Ivor Lewis	Grade V
27.	Mediastinal Tumor Excision	Grade V
28.	Pneumonectomy	Grade V
29.	Total Esophagectom (Transhiatal)	Grade V
30.	Thymectomy	Grade V
	<b>Genitourinary/Gynaecology</b>	
31.	Nephrectomy Radical + IVC Thrombectomy	Grade V
32.	Laparoscopy	Grade V
33.	Ureteroscopy	Grade V
34.	Cystectomy Partial	Grade V
35.	Exploration + Ilco/Colostomy	Grade V
36.	Ileal Conduit (Bladder)	Grade V
37.	Prostate Transurethral Resection of	Grade V
38.	Ureter Resection Anastomosis	Grade V

(To be contd. ...)

## सैलरी बढ़ाने के मुद्दे पर मोदी सरकार ने इसलिए दांव पर लगा दी अपनी लोकप्रियता...

जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो आंकड़ों पर माथापच्ची हुई। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो ये मानते हैं कि इस घोषणा के पीछे अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव हैं। इसमें दोष अनुमानों का नहीं, अनुभवों का है। मनमोहन सिंह की यूपीए-1 सरकार ने छठे वेतन आयोग को जब दो साल की देरी के बाद साल 2008 में लागू किया था तब मूल वेतन में आयोग की सिफारिश की तुलना में दो गुनी बढ़ोतरी कर दी थी। संभवतः यह देरी का पुरस्कार हो, लेकिन साल 2009 के लोकसभा चुनावों में यूपीए-1, विशेषकर कांग्रेस का गठबंधनी बहुमत सुधर गया। यह भी संयोग नहीं है कि यूपीए-2 में मनमोहन सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तब किया जब चुनाव दो महीने दूर थे। लेकिन मोदी सरकार ने सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जो बीते सात दशकों में सबसे कम है। तो क्या मोदी सरकार ने लोकप्रियता पर वित्तीय अनुशासन को तरजीह देने का जोखिम उठाया है?

इसका जवाब हां, तो नहीं है लेकिन यह एक ऐसा दौर जरूर है जब प्रधानमंत्री की अपील पर देश के एक करोड़ से अधिक लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है। आम गैरसरकारी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखें तो पता चलता है कि वे वेतन आयोग की सिफारिशों से असंतुष्ट होने वाले कर्मचारियों के संगठन द्वारा हड़ताल के आह्वान से निराश हैं। यह तकनीकी बात है कि वेतन आयोग की सिफारिशें दस सालों पर आती हैं लेकिन महंगाई भत्ता तो हर साल दो बार नियमित तौर पर बढ़ाया जाता ही है, जिससे वेतन बढ़ता रहता है। नई घोषणा में सरकारी कर्मचारियों को ताजा वेतन बढ़ोतरी से इतर ग्रेज्युटी को 20 लाख रुपये तक करने और नए मकान खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक निकालने की सुविधा मिली है लेकिन असंतुष्ट कर्मचारियों के संगठन की मांग यह भी है कि कार्यकाल के पूरे दौर में कम से कम पांच प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये हो। हालांकि ये मांगें कमजोर दलीलों पर आधारित हैं।

कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अंतर को कम करने की बात कही है। यह समाजवादी विचारों के हिसाब से एक आदर्श स्थिति हो सकती है लेकिन इसके उलट हकीकत यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच आय की असमानता 1990 के दशक के बाद बदस्तूर तेजी से और चिंताजनक रूप से बढ़ी है। आय की असमानता के तर्क अलग-अलग पदों पर चयनित होने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और पद में निहित जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हैं। केंद्र व राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मानकों पर कई दूसरी राहों का ऐलान करती रहती हैं। लेकिन, जिस देश में केंद्रीय कर्मचारियों का सालाना वेतन औसत (साल 2012-13 के आधार पर) 3.92 लाख रुपये हो, वहां वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों का

कितनी बढ़ेगी सैलरी	
बेसिक अभी	लागू होने के बाद
7000	18000
13,500	40,500
21,000	63,000
46,100	2,20,000
90,000	2,50,000

असंतोष काफी कम वेतन और सुविधाओं पर काम करने वाले गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र के कामगारों और किसानों कर रहे करोड़ों लोगों के प्रति असंवेदनशीलता को जताता है। निचले कर्मचारियों और ऊपरी अधिकारियों के वेतन की असमानता यदि एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष यह भी है कि निचले और मध्यम स्तर पर (जो कुल केंद्रीय कर्मचारियों में लगभग 80 प्रतिशत है), निजी क्षेत्र में समान पद पर काम करने वालों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को भारी बढ़त है। दिलचस्प यह है कि शीर्ष पदों पर यह अंतर निजी क्षेत्र के पक्ष में है।

## 7वें वेतन आयोग में उलझे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब यहां हैं

नई दिल्ली: 7वें वेतन आयोग (पे कमिशन) नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने लागू कर दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित एक फैसला लिया और इन सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी। वेतन आयोग पर अभी क्या है स्थिति? रिपोर्ट के लागू होने के बाद करीब 33 लाख कर्मचारियों ने नाखुशी जाहिर करते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जो अब 4 महीने के लिए टल गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वह रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और सरकार के पास न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित दो मांगें रखी हैं। गतिरोध दूर हुआ? बातचीत अभी जारी है दोनों ओर से कुछ झुकने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान 22-23 हजार रुपये करने की बात कही है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस पर तैयार नहीं है... बातचीत अभी जारी है। इस बीच लोग अभी भी रिपोर्ट में दी हुई बातों को लेकर असमंजस में हैं और उन्हें कुछ मुद्दे साफ नहीं हैं। अगर सरकार की सिफारिशों और वर्तमान सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए तो कुछ बातें इस प्रकार हैं... वेतन और भत्तों में कितनी हुई बढ़ोतरी? वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक सैलरी और भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है वह कुछ इस प्रकार है। बेसिक सैलरी में वृद्धि - 16 प्रतिशत, भत्तों में बढ़ोतरी - 63 फीसदी सैलरी और भत्तों को मिलाकर कुल बढ़ोतरी - 23.55 प्रतिशत जहां तक भत्तों की बात है तो कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस से मिली है। सरकार ने एचआरए में करीब 139 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्तों पर गौर किया और इन्हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 51 भत्तों को समाप्त करने और 37 भत्तों को समाहित करने की सिफारिश की है जिसे सरकार ने मान लिया है। पेंशनभोगियों के लिए क्या किया वेतन आयोग ने? वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद पेंशनभोगियों के खाते में पहले की तुलना में 24 फीसदी रकम ज्यादा आएगी। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान सरकार ने कितना किया था फिक्स? सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश और सुझाव को मानते हुए यह नीतिगत फैसला लिया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन तय होगा। वर्तमान तय दर के अनुसार यह इस प्रकार है - न्यूनतम वेतनमान - 18000 रुपये महीना कर्मचारियों के लिए अधिकतम सैलरी - 2.25 लाख रुपये महीना कैबिनेट सचिवों के लिए - 2.5 लाख रुपये महीना न्यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्यूनतम स्तर पर किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा। इसे ही 26 हजार रुपये प्रतिमाह पर ले जाने की बात कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। क्लास वन अधिकारी का न्यूनतम वेतनमान कितना है? उधर, नवनियुक्त 'क्लास-1' अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी 'क्लास-1' अधिकारी का वेतन न्यूनतम स्तर पर नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कुछ बदलाव हुआ है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सरकार ने वेतन आयोग के सुझावों के विपरीत स्वीकार किया है। यह योजना पूर्व की भांति यथावत रहेगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफारिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी। सालाना इंक्रीमेंट कितना होगा? सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को सालाना 3 प्रतिशत की दर से इंक्रीमेंट दिया जाता रहेगा। मिलिट्री सर्विस पे क्या बदलाव हुआ है?

सेना से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकार ने मिलिट्री सर्विस पे को 15500 रुपये प्रतिमाह तय कर दिया है। वेतन आयोग पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें वेतन आयोग सिफारिशों के लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा। वेतन आयोग ने जो वेतन वृद्धि की सिफारिश की है वह पिछले सात दशक में सबसे कम है। लेकिन यह भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत है। बता दें कि सरकार हर दस साल में अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए आयोग का गठन करती है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर फ़ैसला लेती है। 7वें वेतन आयोग (पे कमिशन) के ऐलान के बाद केन्द्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के विरोध का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। 11 जुलाई को हड़ताल के ऐलान के बाद दबाव में आई केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मांगों पर उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है।

## Gazette Notification for implementation of 7th CPC

Dear colleagues

There are lot of discussions about the date of Gazette Notification for implementation of 7th CPC & Office Memorandum, It usually takes about 15 to 20 days after cabinet approval

<b>Fixation of Pay as per the recommendations of 7th Pay Commission</b>					
Initial Appointment on or after 1.1.2016 may be fixed as follows...					
<b>PB 18000/92300 - EP 18000 To 29200 - Level 1 To 5</b>					
Level	1	2	3	4	5
Entry Pay	18000	19900	21700	25500	29200
<b>PB 35400/167800 - EP 35400 To 53100 - Level 6 To 9</b>					
Level	6	7	8	9	
Entry Pay	35400	44900	47600	53100	
<b>PB 56100/209200 - EP 56100 To 78800 - Level 10 To 12</b>					
Level	10	11	12		
Entry Pay	56100	67700	78800		
<b>PB 118500/218200 - EP 118500 To 144200 - Level 13 To 14</b>					
Level	13	13A	14		
Entry Pay	118500	131100	144200		
<b>PB 182200/250000 - EP 182200 To 250000 - Level 15 To 18</b>					
Level	15	16	17	18	
Entry Pay	182200	205400	225000	250000	

of the pay commission report .Let us examine the 6th CPC dates. The union cabinet gave its approval for implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission on 14th August 2008. Gazette Notification for implementation of 6th CPC was issued on 29th August 2008 & Office Memorandum was issued on 30th August 2008, after 16 days after cabinet approval The 7th CPC The union cabinet gave its approval for implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on 29th June 2016. Hence the Gazette Notification for implementation of 7th CPC & Office Memorandum is likely issued in next week.